

प्रेस विज्ञप्ति

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला, मीडिया प्रभारी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं श्री जयवीर शेरगिल, राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निम्नलिखित बयान जारी किया :-

05 नवंबर, 2017

“भाजपा की दीमक” लाई बेरोजगारी, भ्रष्टाचार व महंगाई

“भाजपा ने किया हिमाचल से धोखा व छल”

‘नोटबंदी व जीएसटी की दोहरी मार, जनता कर रही हाहाकार’

41 महीने में मोदी सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लोगों से धोखा, छल व प्रपंच किया है। भाजपाई कुशासन में किसान आत्महत्या की ड्योढ़ी पर खड़ा है, नौजवान बेरोजगारी की मार झेल रहा है, सैनिक भाजपाई उत्पीड़न का शिकार है, बेलगाम महंगाई से आम जनमानस पिस रहा है, व्यापार व व्यवसाय ठप्प पड़ा है तथा अर्थव्यवस्था ICU में हैं। इनका खामियाजा – ‘भुगत रहा है देश व हिमाचल प्रदेश’।

महंगाई अपरंपार, जनता की न सुन रहे गुहार:

मोदी सरकार ने रसोई गैस की कीमतें 16 महीने में 19 बार बढ़ाकर गृहणियों के बजट की कमर तोड़ डाली है। जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतें 35 प्रतिशत कम हो गईं। देश में 18.11 करोड़ सब्सिडाईज्ड गैस उपभोक्ताओं की जेब काटकर भाजपा सरकार ने गैस सिलेंडर की कीमत, जो मई, 2014 में ₹412 थी, बढ़ाकर ₹484.50 कर दी है। यह ₹72.50 की बढ़ोत्तरी है। इसी प्रकार नॉन-सब्सिडाईज्ड घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत तो 11 महीने में ₹152 प्रति सिलेंडर बढ़ा दी। (जनवरी, 2017 में ₹37.50 से बढ़कर नवंबर, 2017 में ₹789.50)

दूसरी ओर मोदी सरकार की मुनाफाखोरी का आलम यह है कि अकेले पेट्रोल/डीजल पर टैक्स लगा आम जनता से ₹2,67,000 वसूले जा रहे हैं। मई, 2014 में मोदी सरकार के गठन के बाद कच्चे तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 52 प्रतिशत गिरे हैं। परंतु 41 महीने में भाजपा सरकार ने पेट्रोल/डीजल पर ‘Excise Duty’ 11 बार बढ़ा दी। मई, 2014 के बाद डीजल पर एक्साईज ड्यूटी में 400.86 प्रतिशत बढ़ोत्तरी व पेट्रोल पर 133.47 प्रतिशत बढ़ोत्तरी की गई। यदि कच्चे तेल के घटे दामों का फायदा जनता को मिलता, तो डीजल की कीमतें ₹30.34 प्रति लीटर व पेट्रोल की कीमतें ₹39.04 प्रति लीटर होतीं।

देश में 7.75 करोड़ परिवार आज भी मिट्टी का तेल इस्तेमाल करते हैं। मोदी सरकार ने तुगलकी फैसला करते हुए मिट्टी तेल की सब्सिडी खत्म करने का निर्णय लिया है, जिसका बोझ सबसे गरीब व्यक्ति पर पड़ेगा।

साधारण जनमानस पर दोहरी मार मारते हुए मोदी सरकार ने एक तरफ तो बैंक के द्वारा दी जाने वाली ब्याज की दरें कम कर दीं, तो दूसरी तरफ ATM कार्ड व बैंक खातों से खुद का रुपया निकलवाने व जमा करवाने पर भी ‘टैक्स’ लगा दिया। उदाहरण के तौर पर एसबीआई द्वारा ‘Savings Account’ (बचत खाते) में ब्याज की दर मई, 2014 में 4 प्रतिशत से घटाकर 3.5 प्रतिशत कर दी गई। एसबीआई में 37 करोड़

खाताधारकों का ₹9.4 लाख करोड़ जमा है। 0.5 प्रतिशत ब्याज दर कम करने से इन 37 करोड़ खाताधारकों को ₹4700 करोड़ सालाना का नुकसान हुआ।

इसी प्रकार 'Public Provident Fund' के 9 करोड़ खाताधारकों को मिलने वाले ब्याज की दर मई, 2014 में 8.7 प्रतिशत से घटाकर 7.8 प्रतिशत कर दी गई है। 'किसान विकास पत्र' के ब्याज की दर साल, 2014 में 8.67 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत कर दी गई। बेटियों के लिए बनाई गई 'सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना' की दर भी साल, 2014 में 9.1 प्रतिशत से घटाकर 8.3 प्रतिशत कर दी गई।

हद तो तब हो गई, जब खुद का पैसा बैंक व एटीएम से निकलवाने तथा जमा करवाने पर भी भाजपा सरकार ने टैक्स लगा दिया। 1 अप्रैल, 2017 से तीन बार से अधिक बैंक खाते/एटीएम से पैसा निकलवाने तथा जमा करवाने पर हर बार ₹100 का टैक्स देना पड़ेगा, जिसे अब लोग मोदी टैक्स कहने लगे हैं। सच यह है कि - "सूट-बूट सरकार, करती जनता की गाड़ी कमाई पर वार"।

जीएसटी अब बना 'गब्बर सिंह टैक्स'

'एक देश, एक टैक्स' के नाम पर मोदी जी ने सात से अधिक टैक्स दरें लागू कर डालीं। यह दरें (0.25 प्रतिशत, 3 प्रतिशत, 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत, 28 प्रतिशत और 40 प्रतिशत) दुनिया में सबसे अधिक हैं। भाजपा ने 'रोटी, कपड़ा और मकान' पर बेतहाशा टैक्स लगा आम जनमानस की कमर तोड़ दी है। क्या भाजपा बताएगी कि रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों जैसे शैंपू/डिटरजेंट/एसी/टीवी/वॉशिंग मशीन/फर्नीचर/कंप्यूटर/टेलीफोन/आईस्क्रीम/ हेयर ऑईल/टूथपेस्ट/सूप/कॉर्न पलेक्स/इंश्योरेंस/ होम लोन/टेक्सटाईल/ब्लड टेस्ट/एक्सरे/अल्ट्रा साउंड आदि पर 28 प्रतिशत व 18 प्रतिशत टैक्स क्यों लगाया? क्या भाजपा बताएगी कि कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग व आभूषण उद्योग पर टैक्स लगा उसे बंद करने की कगार पर क्यों खड़ा कर दिया गया? खेती पर पहली बार टैक्स क्यों लगाया गया? सच्चाई यह है कि भाजपा द्वारा लागू किया जीएसटी है, 'टैक्स का जंजाल, जनता महंगाई से बेहाल'।

मोदी सरकार ने हिमाचल का 'विशेष राज्य का दर्जा' खत्म किया:

साल 2015 में श्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों के 'विशेष राज्य का दर्जा' खत्म कर दिया। सत्ता के शतरंज की झूठी गोदियां बिठाने के लिए अप्रैल, 2017 में इसे फिर बहाल किया गया।

मुख्यमंत्री, श्री वीरभद्र सिंह ने मोदी सरकार से "विशेष श्रेणी पर्वतीय राज्य" के दर्जे की राशि देने का कई बार अनुरोध किया, जिसे मोदी जी ने ठुकरा दिया। पूर्व केंद्रीय कांग्रेस सरकार द्वारा मंजूर कर 90:10 के अनुपात में 2767 करोड़ रु. की राशि 2014-15 में मिली। इसके बाद आज तक हिमाचल को केंद्रीय सरकार द्वारा फूटी कौड़ी नहीं दी गई। मोदी सरकार द्वारा यह हिमाचल के लोगों के साथ किया गया अक्षम्य छल है।

2014 में हिमाचल से किए 'वादों की झूठ' का जवाब दें मोदी जी

मई, 2014 के लोकसभा चुनाव में श्री नरेंद्र मोदी 'सपनों के सौदागर' बनकर आए व अनेकों लोकलुभावन वादे किए। देवभूमि के लोग पूछ रहे हैं :-

1. **29 अप्रैल, 2014** को सोलन रैली में मोदी जी ने वायदा किया कि उनकी सरकार बनने पर सेब के आयात पर 'इंपोर्ट ड्यूटी' (आयात शुल्क) कई गुना बढ़ा दी जाएगी, ताकि सेब उत्पादकों को संरक्षण मिले। अब मोदी जी के शासन में 3 लाख टन से अधिक सेब अमेरिका/चीन/न्यूजीलैंड से आ रहा है, पर मोदी जी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। यह छल क्यों?
2. **29 अप्रैल, 2014** को मोदी जी ने पालमपुर की रैली में हिमाचल को 'पर्यटन का स्वर्ग' बना सबको रोजगार दिलवाने का वायदा कर डाला। 41 महीने में मोदी सरकार ने हिमाचल को पर्यटन के नाम पर न फूटी कौड़ी दी, न कोई नया प्रोजेक्ट। ऐसा प्रपंच क्यों?
3. **29 अप्रैल, 2014** को मंडी में मोदी जी ने कहा कि उनकी सरकार बनने पर चंडीगढ़ से लद्दाख तक हिमालय रेल नेटवर्क बनाएंगे। 41 महीने बाद रेल मंत्रालय का जवाब है कि ऐसा कोई विचार नहीं। यह धोखा क्यों?
4. **27 अप्रैल, 2017** को मोदी जी ने 'उड़ान' स्कीम (उड़े देश का हर नागरिक) की शुरुआत दिल्ली-शिमला उड़ान से कर टिकट का रेट 2036 रुपया बताया व कहा कि अब हवाई चप्पल पहनने वाला हर व्यक्ति हवाई जहाज में सफर कर सकेगा। पर 6 महीने बाद नतीजा यह कि दिल्ली-शिमला जहाज या तो चलता नहीं और चलता है तो टिकट का दाम ₹15000 से अधिक है। यह कपट क्यों?

अब मोदी जी 'जुमलों की बानगी' के निर्विवादित सरदार बन गए हैं।

नोटबंदी का तुगलकी फैसला बना- 'सुनियोजित लूट' व 'जेब पर डाका'

श्री नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास में दूसरे 'मुहम्मद-बिन-तुगलक' के तौर पर जाने जाएंगे। क्योंकि मोदी जी की नोटबंदी ने देश में की तालाबंदी। सच कहा है, नोटबंदी है, 'मोदी निर्मित आपदा' (Modi Made Disaster)।

क्या श्री नरेंद्र मोदी व भाजपा बताएंगे:-

8 नवंबर, 2016 को चलन में ₹44 लाख करोड़ में से ₹15.28 लाख करोड़ यानि 98 प्रतिशत पैसा वापस आ गया, तो फिर बैंकों की लाइन में खड़े 150 निर्दोष लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? छोटे, लघु उद्योगों व असंगठित क्षेत्रों में 3.72 करोड़ लोगों की नौकरियां छीनने का जिम्मेदार कौन है? देश की GDP में 2 प्रतिशत का घाटा कर (9.2 प्रतिशत से 5.7 प्रतिशत) लोगों की आय को 3 लाख करोड़ से अधिक का नुकसान पहुंचाने का जिम्मेदार कौन है?

वास्तविकता यह है कि भाजपा व मोदी सरकार का जनविरोधी चेहरा बेनकाब हो चुका है। देवभूमि हिमाचल की जनता भाजपा को छल, कपट, प्रपंच, व धोखे का करारा जवाब देगी।

जीतेगी कांग्रेस, जीतेगा हिमाचल।